CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Calling Attention to matter of urgent public importance. Shri Dilip Kumar Tirkey to call the attention of the Minister.

Construction of barrages by Chhattisgarh Government on Mahanadi river affecting farmers in Odisha

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): सर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी नदी पर ओडिशा के किसानों को प्रभावित करने वाले बांध के निर्माण की ओर मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान): महोदय, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Where is the statement, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Copies of the statement may please be supplied.

श्री जयराम रमेश (कर्णाटक): सर, यह अंग्रेज़ी में है, हिन्दी में नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इसकी हिन्दी कॉपी कहाँ है? Where is the Hindi copy?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh wants in Hindi!

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, जयराम रमेश जी इसकी हिन्दी कॉपी माँग रहे हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। ...**(व्यवधान)**... जय राम जी की।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Tirkey, you can seek clarifications.

श्री दिलीप कुमार तिर्की: सर, महानदी हमारे ओडिशा राज्य की लाइफलाइन है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tirkey, just one second. ...*(Interruptions)*... Just one second, please.

Mr. Minister, you have supplied the copies of the statement just now. So, it would be better if you read the statement because Members did not get any time to read it.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SUSHRI UMA BHARATI): Sir, it has already been laid on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It has been provided just now. The hon. Members did not get any time to go through it. So, it would be better if you read it.

SUSHRI UMA BHARATI: Okay, Sir.

The Central Water Commission, under the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, carries out techno-economic appraisal of major and medium irrigation projects which are planned on inter-State rivers/ river-basins. After techno-economic appraisal by the Central Water Commission, the project is considered for acceptance by the Advisory Committee in this Ministry. A project should be taken up only after techno-economic appraisal by the CWC and acceptance by the Advisory Committee. The Techno-economic appraisal/ approval of minor irrigation projects (command area less than 2000 hectare) are carried out by the concerned State Government.

Three project proposals, namely Pre-feasibility Report of Tandula Reservoir Augmentation Project and Sondur Reservoir Project and the Detailed Project Report (DPR) of Apra Bhaisajhar barrage project have been received by the Central Water Commission. The project proposals are under appraisal by the CWC. The project proposals are under appraisal by the CWC.

The Memorandum of Agreement entered into between the States of Madhya Pradesh and Odisha on 28.04.1983, *inter alia,* provides for establishment of a Joint Control Board to review the progress, from time to time of survey, investigation, planning, execution and preparation of Joint Inter-State Irrigation and/or Power Project(s) and to discuss and resolve any issue. However, the said Board has not been constituted so far.

An inter-State meeting with the representatives of States of Odisha and Chhattisgarh was scheduled on 27.06.2016 in CWC to discuss inter-State issues concerning projects in Mahanadi basin. However, the same has been postponed at the request of the Government of Odisha.

A meeting under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, with Chief Secretaries of both the States has been scheduled on 29.07.2016 to consider various water resources issues/projects in Mahanadi Basin.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I think the Statement itself is sufficient.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, fine. Now, Mr. Tirkey.

श्री दिलीप कुमार तिर्की : सर, महानदी हमारे ओडिशा के लिए लाइफ लाइन है, लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट्स की दो-तिहाई जनसंख्या इस महानदी के पानी के ऊपर निर्भर करती है। हीराकुड डैम, जो कि Temple of Modern India के रूप में माना जाता है, उसका पानी लास्ट 10 सालों में घट गया है, नदी का जो inflow of water है, वह एक-तिहाई घट गया है। इससे हम चिंतित हैं। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट महानदी के ऊपर 10 बड़े-बड़े बैराज प्रोजेक्ट्स बनाने जा रही है। इनमें से दो-तीन लगभग complete हो चुके हैं। हमारे लिए काफी चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स का जब कंस्ट्रक्शन किया, अभी वे उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी करने जा रहे हैं। कभी भी उसने ओडिशा गवर्नमेंट से न ही कंसल्ट किया और न ही इसके बारे में इन्फार्म किया। यह हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक और आपत्तिजनक बात है।

महोदय, यह हमारे ओडिशा के लगभग 50 परसेंट लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, 65 परसेंट लोगों को indirectly affect करेगा। इससे एग्रीकल्चर में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके कारण सिंचाई प्रभावित होगी। हमारे जो हजारों फिशरमैन हैं, वे प्रभावित होंगे। इसके साथ ही ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत होगी और पानी का जो प्रवाह है, वह भी कम हो जाएगा। इसके कारण पावर जेनरेशन में दिक्कत होगी। इसके कारण काफी कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि inter-State Water Dispute Act, 1956 के तहत अगर कोई अपस्ट्रीम स्टेट में पानी लेना चाहता है, तो उससे डाउनस्ट्रीम स्टेट को इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ओडिशा गवर्नमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म किया था? अगर नहीं किया था, तो क्यों नहीं किया था?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट महानदी के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रही है या बना चुकी है, क्या इन प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेन्ट्रल वाटर कमिशन की अनुमति ली है? अगर नहीं ली है, तो क्यों नहीं ली है? हमारे लिए दुख और आश्चर्यजनक बात यह है कि सेन्ट्रल वाटर कमिशन सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल वाटर कमिशन क्यों चुप बैठा है?

महोदय, 1983 में ओडिशा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जे.बी. पटनायक और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री अर्जुन सिंह के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में ज्वाइंट कंट्रोल बोर्ड बना था कि भविष्य में महानदी के ऊपर जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, वह इस समझौते के तहत इसी बोर्ड की देखरेख में होगा। यह नियम भी नहीं माना गया। इस नियम का भी सीधा-सीधा उल्लंघन किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि यूर्नियन गवनमेंट इसके बारे में क्या कार्रवाई करने जा रही है? और सेंट्रल वाटर कमीशन भी क्या कार्यवाही करना चाह रहा है? महोदय, अब महानदी को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच काफी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, काफी डिस्प्यूट्स होने जा रहे हैं। इस मामले में भी मैं जानना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे क्या कदम उठा रही है? हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिख कर रिक्वेस्ट की थी कि जो ऑनगोइंग इल्लीगल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तुरन्त बंद किया जाए। हम भी यही चाहते हैं तथा हमारी भी यही

[श्री दिलीप कुमार तिर्की]

डिमांड है कि जितने इल्लीगल प्रोजेक्ट्स वहां पर बने हुए हैं या चल रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके, उनको बंद किया जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो वाटर फ्लो होता है, उसको भी एनश्योर करना चाहिए तथा उसे बंद न किया जाए।

महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जितने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनको लेकर उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट बना लिए हैं। इसके लिए उनको सेंट्रल वाटर कमीशन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महोदय, ऐसे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लेकर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना लिए है, जिसके कारण ओडिशा में काफी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो चल रहे हैं, सब को तुरन्त बंद किया जाए, तभी जाकर हमारे ओडिशा के लोग उपकृत हो पाएंगे। थैंक्यू सर।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much Mr. Tirkey. Now, I have nearly a dozen names. Each Member will take two minutes and, in any case, not more than three minutes. Now Shri A.V. Swamy; put your questions.

SHRI A.V. SWAMY (Odisha): Sir, I have been associated with this 'distribution problems' between the Governments of Odisha and Chhattisgarh since 1912 and also directly associated with the people who have been involved in this. Later, I found, I am also a Member of the Standing Committee on Water Resource Development. I have always been trying to raise the issue of whatever projects are being taken should be monitored closely by Central Water Commission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Come to your question because you have only two minutes, maximum three. So come to your question.

SHRI A.V. SWAMY: No, no. I am just trying to give you a background of the entire situation in the area. I think I am the one who is associated directly with the people agitating on the ground. To give you an example, on the 12th of March, 1912, the border area people from both the States, Chhattisgarh and Odisha, came and started shouting about that — for and against. They, at that time, complained that quite a lot of projects are being taken up by the Chhattisgarh Government which will affect the normal flow of water into their territory. That situation has not been explained by the technicians. It is the people who said that they will be affected, and I brought it to the notice of the Central Water Commission also during the Standing Committee meetings to kindly answer this question of the people. But that has not been answered. I am very happy to find a statement by our Chief Minister, Dr. Raman Singh, which is encouraging. At that place, we have mobilized two teams of volunteers. Now they are busy in trying to cool down the people who are at loggerheads about these projects which have been taken up

by the Government of Chhattisgarh. But one very interesting, very welcome thing is the statement made by Dr. Raman Singh in the newspaper. I would read it out, and that too opens up a new channel for us to keep up our relations between Odisha and Chhattisgarh. Sir, since times immemorial, the people of Odisha have had an emotional, cultural and organic relationship with the holy Mahanadi. In fact, what Ganga is to India, Mahanadi is to Odisha. That is the kind of sentiments we have. And if the Mahanadi is being disturbed without consulting the people of Odisha, it might develop into a major mass agitation. A large number of unauthorized projects across the Mahanadi River, reported extensively in the media, give the common man an impression that the Mahanadi would, before long. *...(Time-bell rings)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question. Put the question. Your three minutes are over.

SHRI A. V. SWAMY: No, I don't have a question to put. I want to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Then, you can sit down. It is three minutes now.

SHRI A. V. SWAMY: No, Sir. I want the House to know what is happening there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That provision is not there in Calling Attention. If you want the House to know all the details, then, you will have to give another notice under some other rule. Here, the rule is very clear, the directions of the hon. Chairman are very clear, that you can seek only clarifications. And that has to be done within three minutes.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, then, let me speak for three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Just look at the board. It is already three minutes.

SHRI A. V. SWAMY: Sir, let me start now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do, Swamyji? Put your question and sit down. You have spoken for three minutes.

SHRI A. V. SWAMY: Tomorrow, there would be an upheaval there, there would be a quarrel between people and we would be losing our friendship...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question now.

SHRI A. V. SWAMY: Let the situation be known.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, you will have to give another notice under some other rule, not under this.

SHRI A. V. SWAMY: Then, Sir, I will pray to all my colleagues...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. They are not deciding it. I am deciding it as per the directions of the hon. Chairman under the rules.

SHRI A. V. SWAMY: I pray, Sir, that there is a danger of turmoil. A big agitation has been going on across the banks of the Mahanadi. Teams from two voluntary agencies have been sent there by me. They are now on the field, trying to silence the people who are agitating. And in such a situation, if you say, "Ask a question", I am not just a politician to get to know that answer and go and talk to the people. I will have to face them there the day after tomorrow, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Sit down now. It is already four minutes. I can't allow you more time. Shri D. Raja; you must conclude within three minutes.

SHRI D. RAJA: Sir, my question is with regard to the first part of the Statement. The Central Water Commission under the Ministry of Water Resources carries out a techno-economic appraisal of major and medium irrigation projects which are planned on inter-State river basins.

Sir, we have several inter-State rivers in the country. When such an appraisal is done, the interests of all the riparian States, whether they are the upper riparian States or the lower riparian States, are taken into consideration. I represent Tamil Nadu in this House. The Cauvery is an inter-State river. The Palar is an inter-State river. Now, there is a conflict between Andhra Pradesh and Tamil Nadu on the issue of Palar because some irrigation projects are being planned by the Andhra Pradesh Government, which affect the interests of Tamil Nadu, particularly the northern part of Tamil Nadu. For several years we could not see even a drop of water in the Palar River. In fact, my village is on the very bank of the Palar River. Now, in such a situation, I would like to ask the Government whether the interests of lower riparian States, like Tamil Nadu, have been taken into consideration.

Sir, I share the concern expressed by the hon. Members from Odisha. It is a lower riparian State that way. Mahanadi is the lifeline of Odisha. I understand that. At the same time, there are similar problems in other parts of the country as well. Would the Ministry and the Government try to evolve a comprehensive and overarching policy, so that a consensus is built and no quarrel on river water takes place, because it leads to conflicts amongst States and amongst people? That should be avoided. We should find a solution.

After all, water is going to be a problem for the entire country in the coming days due to climatic changes, global warming and so many other factors. River water is going to be a problem too. Unless we apply our minds and find a proper solution to our river water disputes, it is going to be a problem. That is why i am asking the Government whether such an appraisal has been done. Did they consider the interests and concerns of the lower riparian States? This is what I would like to know from you as the Government. In this case, it is not only the problem of Odisha, but the problem of Tamil Nadu and several other States as well. So, the Government should have an overall view on this issue. That is what I am trying to say.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for this opportunity. The Palar is an inter-State river and the Cauvery is also an inter-State river.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not the Cauvery. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: The Mahanadi is also an inter-State river. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are an advocate; you know how to link. ...*(Interruptions)*... You can also say the Cauvery is also a nadi. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: So, the Mahanadi is also an inter-State river. Now, as per Article 262, the inter-State Water Disputes Act, 1956 had been passed by this Parliament and the jurisdiction of the Supreme Court was also ruled out. But from the dispute of the Cauvery water I could understand that the provisions of the Inter-State Water Dispute Act, 1956 are not sufficient to solve the problems of inter-State rivers. So, I would like to know from the hon. Minister if the Central Government would bring another legislation or bring amendments to this Act. In Andhra Pradesh, the height of check dam has been increased by the Andhra Pradesh Government unilaterally. Now, the hon. Chief Minister, *Amma,* has written a letter to the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh to reduce the height. As a result, Tamil Nadu people, especially Vellore district people, which also includes Mr. D. Raja's district, will be affected very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has no complaint because he is mostly in Delhi. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Yes; it is a necessity. ...*(Interruptions)*... I would like to know from the hon. Minister whether the provisions of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 will be reviewed by the hon. Minister and whether the hon. Minister will bring out the necessary amendments to this Act. Thank you very much.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, from the statement, I think, certain amusing things can be discovered. There is the Inter-State Water Dispute Act, 1956 which necessitates that any work in inter-State river basin should be done taking into confidence the Governments of both the upstream and downstream territories. It is the mandate of that Act. Secondly, on the same understanding, there was an MoU between the Governments of Madhya Pradesh and Odisha in 1983, which stipulates constitution of a Joint Board. We have a Water Resources Ministry, not in this Government but in successive Governments, over a period of time; there is a Ministry; there is a set-up. It is amazing that till now, the Joint Board, as per the 1983 MoU, was not constituted. What have the successive Ministries done? I am not referring to this Ministry only. It is the 1983 MoU. What are they doing? This kind of inaction, sometimes maybe deliberate inaction for political reasons, is giving rise to a situation where the whole integrity of a State of a federal character like us is getting disturbed, and only slogan of cooperative federalism cannot take us to any solution. I could not understand, despite there being this specific MoU, and i think the Government is aware of that as per the Government statement, how these three or four barrages have started, and they are almost on the verge of completion in the Chhattisgarh side of Mahanadi. What has the Central Ministry done so far? They should have done an exercise, at least, of bringing both the State Governments together to discuss and find a solution. Solution has to be found out. What have they done so far? I think these basic issues need to be clarified. Secondly, the similar problem is there throughout the country on some other rivers, as my colleague has mentioned. There is a problem of upstream and downstream States in the matter of water sharing. In my State, West Bengal, we are the worst victims of that because we are in the downstream. Our Farakka Barrage navigability depth is in serious trouble. Our port in Kolkata is a riverine port and its navigability is in serious disturbance and that problem has been further multiplied by the Government's decision to stop spending on dredging. For a riverine port, it is inevitable to spend money on dredging. Now, they have decided to stop spending for dredging and it is creating a problem. I think, these are the issues where lies the role of the Central Government as a conciliatory mediator between the States which are being affected. Is the Government going to seriously reconsider the present state of their activities, which is practically a state of inaction, as it is very clear in this matter? They should revive themselves and take an urgent step to address the issue. If some construction is going on reportedly in the Chhattisgarh part of it, it should stop immediately. Now, both these meetings are to be held. After the Calling Attention Motion notice had been given, now we find that a meeting is going to take place on 29th July. Two days before, another meeting was fixed, but that has been postponed. So, I think, the

whole idea of these meetings has come up only after this notice for the Calling Attention Motion. These are the areas where it is, basically, a problem of the Central Government's inaction which is creating this complication. Will they review their own activities first to address these basic problems? Thank you.

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो महानदी पर बांध बनाया जा रहा है, उससे ओडिशा सरकार को यह आशंका है कि महानदी पर बांध बनने के बाद उसे कम पानी मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अगर यह बांध बन भी जाती हे, तो 25 परसेंट पानी छत्तीसगढ़ को और 75 परसेंट पानी ओडिशा को मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने दोनों राज्यों को मीटिंग के लिए बुलाया है या बुलाकर इनके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की है, जिससे इस समस्या का समुचित हल निकाला जा सके तथा दोनों राज्यों का हित सुरक्षित हो सके?

उपसभापति महोदय, इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीन राज्य प्रभावित होते हैं। आए दिन टेलीविजन में यह देखने को मिलता है और वहां पर बगल का जिला बडवानी है, जहां के आदिवासी लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन जल में खड़े होकर आंदोलन करते हैं। वे आंदोलन इसलिए करते हैं कि जब बांध बना, तब उनको मुआवजा देने की और विस्थापित करने की, दोनों बातें सरकार ने की थीं, लेकिन आज भी उनको मुआवजा नहीं मिला है, आज भी वे विस्थापित नहीं हो पाए हैं। इसलिए वे जल में खड़े होकर 15-15 दिन, 20-20 दिन आंदोलन करते हैं और टेलीविजन के माध्यम से यह जानकारी आती रहती है। ऐसी स्थिति वहां पर नहीं बननी चाहिए। आप पंजाब की ही बात ले लें। पंजाब और हरियाणा में आज भी सतलुज-यमुना नहर का विवाद है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विवाद को हल करने की पहल करें।

इसके साथ ही साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारें जो बांध नदियों पर बनाती हैं, तो इसके लिए जमीन किसानों की लेती हैं, मजदूरों की, गरीबों की लेती हैं। जो गांव उसमें आते हैं, वे गांव आदिवासियों के आते हैं, दलितों के आते हैं। जब इन गांवों को इसके लिए लिया जाता है, तो उनको पूरा भरोसा दिया जाता है कि आपको दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति में गांव गरीबों के उजड़ते हैं, लेकिन बांध बनने के बाद, ज्यादातर बांधों का पानी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है और किसानों के लिए थोड़े से पानी का ही प्रबंध हो पाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब जमीन किसानों की है, गरीबों की है, आदिवासियों की है, तो उन बांधों का फायदा गरीबों को मिलना चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. You were very specific. Now, Shri D. Bandyopadhyay.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity. I have three short questions, and, so, I will not make a lengthy speech. Firstly, there is a 1983 water sharing agreement between the States of

[Shri D. Bandyopadhyay]

Odisha and Madhya Pradesh dealing with the arrangement of Mahanadi River. Now, at the behest of the Chhattisgarh Government, the inter-State agreement is being encroached upon and by-passed by the Centre. There is a breakdown of all the principles of federalism enshrined in the Constitution. This is not cooperative federalism, about which we hear all the time. This is definitely non-cooperative federalism. Were consultations held with all the relevant stakeholders including the officials of both the State Governments before the Centre decided on this matter? What are the inputs given by the Chhattisgarh Government that merited a unilateral move on the part of the Central Government? Secondly, is the State of Chhattisgarh in breach of the inter-State contract signed in 1983 between Odisha and un-divided Madhya Pradesh? Does the *Mahanadi* basin fall within the ambit of this contract? What steps will be taken by the Centre to ensure that the spirit of federalism is maintained between these two States in resolving these issues? My third and the last question is: what is the nature of the project and whether the Central Water Commission's clearance was obtained for this project? Has the Centre conducted any study to assess the environmental impacts of constructing new barrage projects on the River Mahanadi, and, if so, are these studies available in the public domain? Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Respected Deputy Chairman, Sir, I express my gratitude to you for giving me a chance to call the attention of the Union Water Resources Minister on the riparian complications and the role of the Central Water Commission in the light of the riparian States' concerns about *Mahanadi.* Mahanadi, which is having the riparian location of Chhattisgarh, Odisha, is also having a tail end in Andhra Pradesh. I am the son of the deprived land, that is, Telangana, not because of nature but because of successive Governments of the then united Andhra Pradesh for the sixty long years, and, that is why we are in such a condition that we need to do re-engineering of the engineering done earlier. The Union Minister of Water Resources is well aware, and, fortnightly, she is reviewing this ' with the Ministers of Irrigation of both the States, Telangana and Andhra Pradesh.

Now, the *Godavari* River is on the *Antya-Pushkara.* The *Pushkaras* are to complete in the Godavari, and, from August 12 onwards, the *Pushkaras* will be starting for the *Krishna.* These two Rivers are having the largest catchment area in Telangana wherein we are not in a position to utilize those great waters. Recent rains have flowed several TMCs of water into Godavari wherein more than 300 TMC of water has gone into the sea. With

these situations prevailing upon, the new State of Telangana is intending to utilize the waters for its benefit for coming out of the deprival of all these years. For that, whether the Central Water Commission is technically equipped to assess the techno-economic situations, which are coming out of the urge to utilize the larger chunk of the water share available. Then only, the Central Water Commission can do justice. Now, the Union Ministry of Water Resources has become almost a quasi-judicial Ministry. It is having not only the Central Water Commission, but also several authorities, several tribunals, which are having the powers to give judgements and pronouncements. Keeping these factors into account, the Union Ministry of Water Resources should come out with steps to equip the Central Water Commission and the subsequent tribunals so as to address the water demands. Otherwise, water wars will generate. Thank you.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I don't want to add much to what he has already said because the subject is about river Mahanadi and the Odisha villages that are being affected. I understand that. So, diverting it to what my hon. colleague has said about Telangana would be stretching it too far. My only submission is, let the Water Ministry also understand the riparian rights and also utilize the *ayacuts.* Whereas the other States are interfering, I don't know why I should interfere with their main question. The very fact Mr. Ananda has said in detail. I think I would not add anything more to that. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Dr. Rao. That is a very good example for others that if something is already said, do not repeat it. I think this is a very good example. I should thank you for that. Now, Shri Anubhav Mohanty.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (Odisha): Thank you, Sir, for allowing me. Sir, the process of offering clearance to the major irrigation projects by CWC without informing the State Government of Odisha and without honouring the concern of the people of Odisha is really very alarming and it is putting me in a dilemma. Neither has the DPR been forwarded to Odisha, nor has Odisha been invited to the TAC, that is, the Technical Advisory Committee, which would have been conducted prior to giving clearance to the project. Sir, even during the clearance process from the Ministry of Environment and Forests, a check for obtaining clearance from the co-basin State should have been insisted upon, which has not been done in this instant case. Sir, with the sequel of developments, all to sideline Odisha from its legitimate participatory role, the main question remains that when the CWC which is supposed to play a lead role with respect to preserving order while according clearances by resolving inter-State conflicts flouts the norms as has been done in the instant case, where do the States go

[Shri Anubhav Mohanty]

for redressal? Sir, Mahanadi is the lifeline of Odisha. I, as an Odia, my party, Biju Janata Dal, and the people of Odisha demand an immediate stop on the project by Chhattisgarh in the upper Mahanadi basin. Sir, Odisha feels proud when we talk about two Odia people in the Union Government's Ministries, hon. Shri Dharmendra Pradhanji and hon. Jual Oramji. I request them to stand in favour of Odisha because this is quite a genuine matter, not to politicize anything ...*(Interruptions)*... इसे politicize नहीं करना चाहिए because when they go to Odisha and speak to the people there, they say, "We are always standing for the people of Odisha; we will do anything that is required for Odisha; we will fight for the rights of Odisha." I expect a very favourable stand from, at least, these two Ministers, and I request them to take their position and request the Government to take necessary steps and stop this project as immediately as possible. Thank you, Sir.

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान): डिप्टी चेयरमैन साहब, इस विषय पर अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, यह भारत के किसानों की समस्या है। कुल मिलाकर विषय यह है कि नदी के जल का उपयोग इस प्रकार से हो, जिससे हमारे किसानों की आवश्यकताएं पूरी हों। यह सच है कि इस देश में 89 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिन्हें आज़ादी के बाद आरंभ किया गया और यह उस समय से सत्ता में रहे लोगों के कारण ये 89 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, सबसे पहले बजट में उन 89 परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए हैं। दूसरा एक विषय ...(**व्यवधान**)... जिस विषय पर मैं आ रहा हूँ, वह यह भी है कि 1983 में मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच जो समझौता हुआ था, और आज यह जो विषय आया है, जिस विषय पर माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में भी हा है कि बोर्ड का गठन नहीं हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1983 से लेकर आज, 2016 तक केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्यों में किसकी सरकार थी? हमारे बीजेडी के मित्र हमारे मित्रों के लिए अभी जो कह रहे थे, मैं उस संदर्भ में उनको बताना चाहता हूं कि आपके पास तो एनडीए सरकार में जल मंत्रालय भी था। इतना ही नहीं, आप खुद, 1983 से लेकर... अब लगभग दस साल से ओडिशा में आप सत्ता में हैं, आपने कब इस बात को बहुत जोर से कहा कि यह बोर्ड बनना चाहिए? हम तो केन्द्र सरकार का इस बात के लिए स्वागत करते हैं कि उन्होंने बोर्ड बनाने की पहल की। माननीय मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है, हम केंद्र सरकार को उस बात के लिए बधाई भी देना चाहते हैं कि उन्होंने 27 जून को CWC की मीटिंग बुलाई। वह पोस्टपोन हुई, लेकिन वे इस विवाद का समाधान कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि यह परियोजना सकारात्मक रूप से पूरी होनी चाहिए और इसको संवेदनशीलता का विषय नहीं बनाना चाहिए। दोनों ही प्रदेशों के किसानों को, कुल मिलाकर, सब किसानों को महानदी के बेसिन का फायदा होना चाहिए।

जो minor irrigation project है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बना सकती है, उसको बनाने की संकल्पना में उसके द्वारा केवल एक सीमित सिंचाई क्षेत्र को ही पूरा किया जा रहा है। उसके साथ-साथ दो प्रोजेक्ट्स, जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनको सेंट्रल वॉटर बोर्ड एग्ज़ामिन करे। हमारी सरकार के द्वारा यह जो विषय लिया जा रहा है, निश्चित रूप से इसको करने की कोशिश करनी चाहिए।

हमारा यह भी कहना है कि इस विषय में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि आज़ादी के 70 सालों में आखिर देश की केवल 46 प्रतिशत जमीन ही सिंचित क्यों हो पाई? किसानों की प्राथमिकताओं के जो विषय थे, उनको एक लंबे समय तक हमारी पूर्ववर्ती सरकारारें ने क्यों अनदेखा किया? उस अनदेखी का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ है, उसको हमारे किसानों को भी भुगतना पड़ा है।

जो अंतर्राज्यीय विवाद है, हमें उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। आज महानदी का जो क्षेत्र है, उसका लगभग 53 प्रतिशत क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पड़ता है और 45 प्रतिशत ओडिशा में पड़ता है, लेकिन जब हम प्रमुख रूप से इन दोनों राज्यों के लिए इस विषय के समाधान की बात करना चाहते हैं, तो उसका cumulative effect होना चाहिए और कम से कम ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bhupenderji, okay. ...*(Interruptions)*... You just seek clarifications.

SHRI BHUPINDER YADAV: I have finished. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have 3-4 requests which I received a little late. Because they are all pressing for it, if they confine to two minutes each, I am ready to give them a chance. But, they should confine to two minutes. First, Shri Palvai Govardhan Reddy; absent. Now, Shri Basawaraj Patil. You have two minutes.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): उपसभापति जी, जिस विषय पर Calling Attention Motion आया है, उस विषय पर भुपेन्द्र यादव जी ने कहा है कि यह सारे देश के किसानों की समस्या है, लेकिन कई बार इससे भी बढ़कर, किसी के राइट पर नाम पर, पुराने जमाने में, सौ-डेढ़ सौ साल पहले बने एग्रीमेंट के नाम पर, हमें कई बार पीने के पानी के लिए भी कावेरी नदी पर समस्या को उठाना पड़ता है। इसीलिए समग्र देश के हित को ध्यान में रखते हुए पहली प्राथमिकता पीने का पानी, फिर छोटी सिंचाई योजना और किसी राज्य के किसानों का हित दूसरे के लिए हानिकारक न बने, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना एक विश्वास इस सदन को दे, मैं इसकी प्रार्थना करता हूं।

डा. भूषण लाल जांगडे (छत्तीसगढ़): उपसभापति जी, सबसे पहले ओडिशा में हीराकुड बाँध बना। उसके लिए कोई आपत्ति नहीं हुई थी। यह 1955 या 56 में बन चुका था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में गंगरेल बाँध बना। इस बीच में ऐसा कोई बाँध महानदी पर नहीं बना है। जितने भी बाँध बने हैं, वे बैराज के रूप में बने हैं। जब कभी भी बाढ़ आती है, तो बैराज का पानी उसको रोकता नहीं है। बैराज केवल जल स्तर को सुधारने के लिए बना है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जितने पावर प्लांट्स बने हैं, यह बैराज उनके लिए बना है। इसने आज तक किसी भी तरह से फ्लड को नहीं रोका है और रोकने का सवाल भी नहीं उठता है। जितने भी बाँध बने हैं, इन बाँधों की जितनी नदियाँ हैं, जैसे अरपा नदी है, हसदेव नदी है या अन्य जो भी नदियाँ हैं, वे वहाँ बने हैं, महानदी पर कोई भी बाँध नहीं बना है। ओडिशा सरकार या ओडिशा के हमारे सांसद भाई क्यों आपत्ति कर रहे हैं, यह मेरी समझ के परे है।

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Sir, recently, in the 11th Inter-State Council meeting held on 16th July, our hon. Chief Minister had made it very, very clear and, in front of the Prime Minister, he said, the upper-catchment projects have been undertaken in the Mahanadi Basin without consulting the State. About sixteen of our districts and sixty-five per cent of the population are being affected. And he urged upon the hon. Prime Minister to look into the matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Shri T.K.S. Elangovan. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.U. SINGH DEO: I hope this will be taken note of. Sir, I am still speaking. Just give me one second.

Sir, my younger brother, Bhupender*ji,* said that for some time, the Odisha Government did not take note of things and bring it to the notice of the Government. Sir, just give me one second. In the Polavaram project, which was done by the UPA sarkar, we went before this Government hundreds of times. But they did not take note of it. They are drowning us by the Polavaram project and they are drying us by the Mahanadi project. ये महानदी प्रोजेक्ट करके हमको सुखा रहे हैं। ये पोलावरम प्रोजेक्ट करके हमको डुबा रहे हैं। हम इसको इनके नोटिस में लाते हैं। हमारे मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री की मीटिंग में इसको लाए हैं और इनके सामने रखा है। हम ऑनरेबल मिनिस्टर से आशा रखते हैं कि ये हमें उत्तर देंगी कि जो प्रोजेक्ट्स बन चुके सो बन चुके, जो बनने वाले हैं, जो ओडिशा के बॉर्डर से सटे केलो नदी पर बनने वाला है या जो और प्रोजेक्ट्स कल्पना में है, उनके लिए अपने ओडिशा सरकार को consult किया है या नहीं, ...(समय की घंटी)... पूछा है या नहीं। धन्यवाद।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, this being my maiden speech in this House, i would first like to thank my leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, for having given me a chance to serve the people through this House. Sir, at the outset, the subject was dealt with by many people here. First, the dispute started with Cauvery, then, it came to Mullaperiyar, then to Palar and now to Mahanadi. The water problem is a great problem in this country. It is said that the third world war will be for water. I do not want the Government to-allow the third world war to start in India. That is my request. The Government should intervene. There are issues. Why should you stop water? In Cauvery, particularly, the Delta area had seen three season crops. But, today, it is seeing only one season crop which means it is a two season crop loss to the country, not to the State but to the country. Agriculture is the only area which sustains the economy of India and not industry. If agriculture fails, economy will fall. That should be understood by the Central Government. There are discussions on interlinking of rivers in India. The BJP Government in 1999 had stated that as per the order of the Supreme Court, they would

interlink all rivers in this country. There should be a strong management. What I ask of the Government is this. Please give us back education and take management of water resources. That will save both education and water in this country. With these words, I thank you, Sir.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I was in Odisha over the weekend. Every now and then, the Chief Minister of Odisha raises some issue to divert attention from issues which are agitating the people. We had gone to Kandhamal to investigate and make a report on the killing of three tribals and two *dalits ...(Interruptions)...* in an unprovoked police firing. *...(Interruptions)...*

SHRI ANUBHAV MOHANTY: This is not related to the subject. *...(Interruptions)...*

श्री दिलीप कुमार तिर्कीः सर, वहाँ पर किसी की हत्या नहीं की गई है। **...(व्यवधान)...** कहीं पर किसी की हत्या नहीं की गई है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. *...(Interruptions)...* On this subject. *...(Interruptions)...*

SHRI ANUBHAV MOHANTY: This is not related to the subject. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: However, *...(Interruptions)...* I am supporting you. *...(Interruptions)...*

SHRI ANUBHAV MOHANTY: You are not speaking on this. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not distract. *...(Interruptions)...* Come to the subject. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: When we were there, suddenly the issue of the barrage on the Mahanadi was raised. *...(Interruptions)...*

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Speaking of Odisha, what has your Government done to Odisha? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am not yielding. *...(Interruptions)...* I am not yielding. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to seek clarifications. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: I am seeking clarifications. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not divert the subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: I am asking. ...*(Interruptions)*... If they allow me to seek clarification, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, let him. ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...** Please resume your seat. ...*(Interruptions)*... You seek your clarification. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, the people of Odisha know how their Government has looted Odisha. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is okay. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: So let us not go into those issues. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No problem. Let him seek clarifications. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Chhattisgarh Government. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You know everything. Then, why do you seek clarification?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have to seek clarification. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Chhattisgarh Government has proposed four projects on Mahanadi. This is, undoubtedly, going to have an effect on the River Mahanadi in Odisha. Mahanadi is starting in Chhattisgarh and flowing into the Bay of Bengal. My first question is, a question that was also referred to by Mr. Bandyopadhyay: Have the Chhattisgarh Government and the Union Ministry of Water Resources taken steps to complete an Environmental Impact Assessment of these four projects? That is number one.

Sir, number two is, in our country, water is not a technical subject. Water is a political subject. It has become a political subject because we made the mistake, decades ago, of not including water in the Concurrent List of our Constitution. However, what is done is done. We can't undo it. Since water is a State subject and, since, water has become a political issue, I want to know from the hon. Minister whether she will invite the State

Ministers. This cannot be resolved at the level of Chief Engineers; this cannot be resolved at the level of Secretaries. You have to invite the two Ministers. The Prime Minister has to invite both the Chief Ministers and arrive at a settlement on this issue. So my second question is: Will the Ministers concerned from the two States and the two Chief Ministers be brought for a meeting to resolve this issue?

My final clarification is to my good friend, Mr. A.U. Singh Deo. Polavaram is not killing Odisha; Polavaram is submerging a couple of villages in Malkangiri district, and, whatever steps have to be taken to deal with the impact of submergence, must be taken by the Government of India because Polavaram is no longer a project of the Government of Andhra Pradesh; Polavaram is, now, a Government of India project.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, Polavaram is ...*(Interruptions)*... Not just a few villages ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir ...*(Interruptions)*... Sir ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Palvai, when I called you, where were you? ...*(Interruptions)*... You give the name and run away. ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sorry, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question; that is all. ...*(Interruptions)*... Put one question. ...*(Interruptions)*... There is only one minute.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, the Government of India is not taking proper care about regulation of rivers. Just now, my friend from Odisha raised a subject regarding Polavaram. Polavaram is submerging about 375 villages, not only in Telanagna, but also in Odisha and Chhattisgarh. Therefore, we have given a proposal to them. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your clarification? ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, I am seeking it. We have given a proposal to them, on behalf of myself, and Mr. Hanumantha Rao. We have told very clearly, Polavaram can be constructed through barrages also. That will submerge only 131 villages. Government of India is not at all taking care of it and they are coming under the influence of the TDP, Venkaiah Naidu*ji* and Chandrababu Naidu*ji.* Therefore, I only want to know through you, Sir, whether they will consider this barrage formula or not. Because, now, it is not a project of Andhra Pradesh anymore, it is a project of the Government of India. The Government of India can take a decision. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: And regarding Mahanadi, Sir, I will say only one thing. Mahanadi is a very big river in Odisha and Chhattisgarh. Jawaharlal Nehru laid the foundation of Hirakund Dam. It is giving very good results. But, now, what is happening, Sir, is ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question?

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: I am asking, Sir? The Government of Odisha and Government of Chhattisgarh should sit together and solve the problem. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is fine. ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, there is one more important thing. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a good suggestion. No; that is enough. It is a suggestion. ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Only one point, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I allowed you out-of-turn and you are exploiting that. ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, Mahanadi is polluting. Therefore, industrial pollution or any other pollution should not go into the river. That will destroy the entire flow. Therefore, I only request the Government of India ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Minister ...*(Interruptions)*...

डा. संजीव कुमार बालियानः डिप्टी चेयरमैन साहब, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चार मेजर प्रोजेक्ट्स सीडब्ल्यूसी के पास आए थे। इसके अलावा कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, जो दो हजार हेक्टेयर से कम के हैं, जिनको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन पर प्रदेश सरकार का अपना निर्णय रहना है। तो जो ये चार प्रोजेक्ट्स सीडब्ल्यूसी के पास आए थे, उनमें से केलो डैम 2009 में एप्रूव किया गया था और इसकी सूचना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2006 में ओडिशा सरकार को दी गई थी। यह केलो डैम प्रोजैक्ट 2009 में एप्रूव हुआ था, जिसका बड़ा नाम है। दूसरा टेरी महानदी का प्रोजेक्ट सीडब्ल्यूसी में जमा किया गया। सीडब्ल्यूसी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कहा गया। फिर 4 फरवरी, 2016 को डीपीआर ओडिशा सरकार को कॉमेंट्स के लिए भेज दी गई। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। तंदुला रिज़रवॉयर प्रोजेक्ट, यह सीडब्ल्यूसी में जमा किया गया, ओडिशा सरकार को 2 सितम्बर, 2015 को कहा गया। इसकी डीपीआर ओडिशा सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भेज दी गई है। चौथा प्रोजेक्ट तंदुला प्रोजेक्ट है, इसकी डीपीआर सीडब्ल्यूसी को 2013 को दी गई।

जनवरी, 2014 में सीडब्ल्यूसी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कहा गया कि डीपीआर ओडिशा सरकार को दी जाए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। उसके बाद 2015 में इस तंदुला प्रोजेक्ट की डीपीआर ओडिशा सरकार को दी गई। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। सीडब्ल्यूसी की जो टेक्नीकल एडवायजरी कमेटी है, उसके द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को एप्रूवल नहीं दिया गया है, पहली बात यह है। एक ही प्रोजेक्ट केलो डैम का एप्रूवल 2009 में हुआ था। इस सरकार के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट को, जो टेक्नीकल एडवायजरी कमेटी द्वारा एप्रूवल दिया जाता है, वह इस सवाल दो साल में नहीं दिया गया है। इसके बावजूद तंदुला डैम पर कुछ काम हुआ है, वह बिना एप्रूवल के हुआ है। यह सही है कि यह परिपाटी रही है कि पहले एप्रूवल हो, उसके बाद ही काम शुरू होना चाहिए। अभी तक सवा दो साल में यहां से कोई भी नये प्रोजेक्ट का एप्रूवल नहीं हुआ है, सिवाय केलो डैम के। उसके अलावा जो ऑब्जेक्शंस हैं, वे सभी दो हजार हेक्टेयर से कम के डैम हैं,जो माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए एप्रूवल के लिए यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, कुछ सवाल जो माननीय सदस्यों की ओर से आए हैं। तिर्की जी ने कहा कि पानी का फ्लो वन-थर्ड कम हुआ है। यह ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, पिछले दस वर्षों में फ्लो कम नहीं हुआ है।

श्री दिलीप कुमार तिर्कीः जो हमारे डैम हैं, डैम के नीचे जितने ...(**व्यवधान**)...

डा. संजीव कुमार बालियानः फ्लो कम नहीं हुआ, मैं आपके पास पेपर्स भिजवा दूंगा। दूसरी बात यह किं इफॉर्मेशन ओडिशा सरकार को नहीं दी गई, करीब-करीब सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में सीडब्ल्यूसी के द्वारा कहा गया कि पहले ओडिशा सरकार को इंफॉर्मेशन दी जाए। सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआरर्स ओडिशा सरकार को भेजी गई हैं, जो मुझे सूचना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मिली है, जो विद डेट है। उसके बावजूद अभी तक कोई एप्रूवल नहीं हुआ है। इसलिए आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

श्री अनुभव मोहंतीः मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई डीपीआर रिसीव नहीं की गई, ओडिशा सरकार के पास कोई नहीं आई है No DPR has been received.

DR. SANJEEV KUMAR BALYAN: Already received. छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह सूचना दी गई है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा, उसने आपको सूचना दी है। ...(**व्यवधान**)... एक बात आई, जो ज्वॉयंट ग्रुप की बात थी, 1983 में जो एग्रीमेंट हुआ था, यह ज्वॉयंट ग्रुप बनना चाहिए था, इस बात को 35-36 साल हो चुके हैं, आज तक ज्वॉयंट ग्रुप नहीं बना। इसके लिए कहीं भी केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार का एग्रीमेंट था। उन्हें अपने आप ज्वायंट कंट्रोल ग्रुप बनाना चाहिए था। अगर कहीं यह ज्वॉयंट कंट्रोल ग्रुप बनता, तो शायद यह समस्या आज उत्पन्न नहीं होती। मानसून से महानदी रिवर में जो फ्लो है, उसमें किसी भी डैम से कोई समस्या नहीं है। जो कम से कम ओडिशा की समस्या है, वह मानसून के बाद जो पानी का फ्लो है, वह कहीं बाधित होता है या नहीं, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यह है, सर। ओडिशा सरकार का करीब डेढ़ महीने पहले केन्द्र सरकार को एक पत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद पिछले महीने 27 जून को दोनों सरकारों को कहा गया कि सीडब्ल्यूसी के यहां एक मीटिंग है, आप आइए। छत्तीसगढ़ सरकार से अधिकारी ने कन्सेंट दी कि हम आएंगे।

3.00 P.M .

ओडिशा से यह रिक्वेस्ट आई कि एक महीने का समय दिया जाए, क्योंकि हम एक महीने बाद ही आ सकते हैं। तो इस नोटिस के बाद नहीं या इस मोशन के बाद नहीं, बल्कि इस मोशन के आने से पहले ही केन्द्र सरकार पिछले महीने बैठक बुला चुकी थी। ओडिशा की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि हम एक महीने बाद आएँगे। अभी 29 तारीख को दोबारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों को बुलाया गया है, यानी सेक्रेटरी द्वारा दोनों के चीफ सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया है। सीडब्ल्यूसी या मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सेज़, जब किसी सरकार का पत्र प्राप्त हो, उसके बाद ही इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके बिना इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब पत्र प्राप्त हुआ, तो तुरंत प्रभाव से इंटरफेयरेंस हुआ है।

सर, जहाँ तक एक्ट की बात है, तो 1956 का जो एक्ट है, इसकी बार-बार चर्चा हुई है। वह केन्द्र सरकार को कोई अधिकार नहीं देता कि हम किसी को कानूनी रूप से कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बाध्य कर सकें। हाँ, अगर दोनों राज्य सरकारें आती हैं, तो 29 तारीख को इस पर बातचीत होगी। उसमें प्रयास किया जाएगा कि दोनों से सलाह-मशविरे के बाद इसमें आगे काम शुरू हो। दोनों सरकारों से बात की जाएगी और इसका कोई न कोई हल निकाला जाएगा। सर, अनेक सदस्यों के सुझाव आए कि कानून में संशोधन होना चाहिए। अगर फिर भी इसमें दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है, तो इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत ओडिशा से हमें काई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि ट्रिब्यूनल का गठन हो सके। तो सबसे पहले ओडिशा सरकार को इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। उसके बाद केन्द्र सरकार इसमें एक mediator का रोल प्ले करेगी। अगर मीडिएशन नहीं हो पाया, तो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसमें यही एकमात्र हल है।

श्री दिलीप कुमार तिर्कीः सर ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I want one clarification. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister wants to say something.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I need one minute only. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You listen to the Minister. She wants to speak. ...*(Interruptions)*... She wants to add something. ...*(Interruptions)*...

सुश्री उमा भारतीः सर, माननीय राज्य मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह अपने आपमें सम्पूर्ण है, किन्तु जो दो प्रश्न अनुत्तरित रह गए, मैं उनके उत्तर देना चाहती हूँ।

सर, एक बात तो यह आई है कि हमने बैठक तब बुलाई, जब कोई आपत्ति आई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैठक 26 जून को बुलाई गई और कॉलिंग अटेंशन का जो नोटिस है, वह एक हफ्ता पहले ही लगा है। यानी हमारा इरादा इस विषय में पहले से ही यह था कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बैठक हो जाए, लेकिन ओडिशा की ही रिक्वेस्ट पर वह बैठक एक महीने के लिए पोस्टपोन हो गई। दूसरी बात, जो सदन के एक वरिष्ठ सदस्य, माननीय जयराम रमेश जी ने कही है, कि क्या हमारा जल संसाधन

मंत्रालय दोनों राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक के बारे में विचार कर सकता है, तो वह विचार हम कर चुके हैं। पहले अधिकारियों के लेवल पर बैठक होगी, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी, तो दोनों राज्यों के मंत्री के लेवल पर बैठक होगी। अगर बोर्ड बन गया होता, तो इस समस्या का समाधान दोनों राज्यों ने बैठ कर कर लिया होता।

सर, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अभी पीछे से एक माननीय युवा सदस्य ने यह कहा कि हमारे एक माननीय मंत्री आडिशा के हैं, तो वे ओडिशा की चिन्ता करें। माननीय उपसभापति महोदय, ओडिशा से प्यार करने के लिए ओडिशा में पैदा होने की जरूरत नहीं है, भारत में पैदा होना ही काफी है। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्यः वह मंत्री जी अभी यहाँ नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

सुश्री उमा भारतीः उनकी जरूरत भी नहीं है। ...(**व्यवधान**)... क्योंकि भारती यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी जरूरत नहीं है। हम ओडिशा से बहुत प्यार करते हैं। हमें ओडिशा की बहुत चिन्ता है। हम ओडिशा के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करती हूँ कि 29 तारीख की बैठक के बाद भी यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो जल संसाधन मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी तथा ओडिशा और छत्तीसगढ़ का यह जो मसला है, इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यों को और सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ कि इस समस्या का समाधान हम ऐसा ही निकालेंगे, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें कहा है - 'सबका साथ, सबका विकास'। ...(**व्यवधान**)... इसलिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी चिंता करेंगे और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ओडिशा से प्यार करने के लिए ओडिशा में पैदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओडिशा भगवान जगन्नाथ का राज्य है, जगत के नाथ का राज्य है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिलीप कुमार तिर्की : सर ...(**व्यवधान**)... सर, हम लोग मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Just one minute, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is enough. ...*(Interruptions)*... That is okay. ...*(Interruptions)*...

SHRI DILIP KUMAR TIRKEY: Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Just one clarification. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No clarification over clarification! ...*(Interruptions)*... No clarification over clarification. ...*(Interruptions)*... आप मेरी बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Mr, Anubhav, she said that the interests of Odisha would be taken care of. That is an assurance. That is enough. You sit down now. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... That is enough. ...*(Interruptions)*... No, no. That is enough. Now, Papers to be laid on the Table. ...*(Interruptions)*... There is an item in the Supplementary List of Business, for Papers to be laid on the Table. If the House agrees, I will call the Minister. ...*(Interruptions)*... Now, Papers to be laid on the Table, Shri Santosh Kumar Gangwar.